and constitute a committee to monitor the old age homes, thereby ensuring quality of life for the elders, the so-called senior citizens.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with it.

**Plight of disabled persons**

**श्री रुमान्डला रामचन्द्रय्या** (आंध्र प्रदेश) : सभापति महोदय, देश में विकलांग व्यक्तियों की हालत बहुत दयनीय है । वे लोग बहुत कठिनाई का जीवन जी रहे हैं, जबकि वे सहायता तथा सहानुभूति के पात्र हैं । उन्हें सुखी जीवन जीने के लिए मुहैया कराई गई सुविधाएं नगण्य हैं । सरकार को उनकी ओर ध्यान देकर उन्हें आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिए । देश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उन लोगों को मूलभूत सहूलियतें बहुत कम दी जा रही हैं । समाज में उनकी मुश्किलों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है । एक विकलांग व्यक्ति को समाज पर बोझ माना जाता है। लोग समझते हैं कि उस व्यक्ति को धन अर्जित करने वाला होना चाहिए, चाहे उसमें चलने की सामर्थ्य न हो, चाहे वह व्हील चेयर पर जाता हो । आवश्यकता इस बात की है कि समाज उस अभागे व्यक्ति की ओर ध्यान दे ।

उन लोगों के अपने गुण होते हैं। वे लोग परिश्रमी होते हैं और पूरी निष्ठा से काम करते हैं, जो उनको सौंपा जाता है। कुछ कम्पनियों ने इन लोगों को अपने यहां भर्ती किया है और उनका अनुभव है कि ये लोग अत्यंत अच्छे कार्यकर्ता हैं। इन कंपनियों ने इन लोगों को आवश्यक सुविधाएं जैसे कार्य के स्थल पर रैम्प बनवाना, रेलिंग और विशेष प्रकार से बनाए गए शौचालय निर्मित किये हैं। इन विकलांग लोगों को इनके कार्य के स्थान पर, भूतल पर खाना मुहैया कराया जाता है। सरकार ने इन लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया था, परन्तु खेद की बात है कि इसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह प्रावधान निरर्थक सिद्ध हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाए जो यह सुनिश्चित करे कि सरकारी नीति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को समुचित स्थानों पर भर्ती किया जाए। केन्द्रीय सरकार को विकलांग बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा आदि का व्यय सहन करना चाहिए। इसके लिए राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राजनीतिक निकायों में स्थान आरक्षित किया जाए। आरम्भ में तो पंचायतों में कुछ स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। बाद में राज्य विधान सभाओं और संसद में भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। धन्यवाद।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with this Special Mention. However, I would like to mention only one point. This is an important issue. Through this Special Mention, the pitiable condition of the disabled children has been highlighted. I would request the Minister of Rural Development, Shri M. Venkaiah Naidu, to put a word to the Minister of Social Welfare so that some schemes can be started for these children.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, I have taken note of the suggestion. I will convey it to the concerned hon. Minister.

**Statement of U.S. Under Secretary of Defence on Apprehension of Indo-Pak War**

SHRI K.M. KHAN (Andhra Pradesh): Sir, I wish to draw the attention of this House to the reported statement of the US Under Secretary of Defence, Mr. Douglas Feith, who, in a Conference on US- Indian Defence Trade said, "There is a risk of war. You are talking about two countries which are armed with nuclear weapons. So the risks are very high. We are focussing on defusing those tensions." He further said, "We are focussed intensely on this issue of India and Pakistan and the Kashmir problem, and the dangers from mobilisation that has taken place there." The U.S. Assistant Secretary of State, Ms. Christina Rocca, arrived in Delhi to reduce the risk of Indo-Pak war. Sir, the United States of America is working hard on Indo-Pak relations and on the problem of Kashmir. The statement of the U.S. Under Secretary of Defence is of a serious nature. What is the basis of American apprehension on Indo-Pak war? The United State of America is showing unusual interest in Kashmir. This is a serious matter because we believe that Kashmir is a bilateral issue. There is no scope for the third party intervention in Kashmir. In this background, the visit of Ms. Rocca is an effort of the U.S. interference in our internal affairs. Is it not a departure from our accepted foreign policy? I would request the hon. Minister of External Affairs and the hon. Prime Minister to protect our national interest, while dealing with the situation, and make a statement on this issue.

Sir, I would just like to add one more thing that despite the heinous killings of our Jawans and their families that took place yesterday in Jammu, it is unfortunate that the highest level of the U.S. Administration has not made any condemnation of the incident.

On the other hand, Miss Christina Rocca maintains the position that President Musharraf is doing his best to deal with terrorism. This is a serious matter. I want the hon. Foreign Minister or the Prime Minister to make a statement on this.

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has stated.